भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2533

दिनांक 10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन

2533. श्री संदोष कुमार पी:

क्या ***योजना*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने विगत पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों में आर्थिक संवृद्धि, अवसंरचना तथा मानव विकास में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताओं का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो, प्रमुख विकास संकेतकों पर केरल राज्य की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतर-राज्यीय विकास संबंधी असमानताओं के समाधान के लिए कोई लक्षित कार्यनीति अथवा विशेष सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान नीति आयोग द्वारा केरल के लिए अनुशंसित परियोजनाओं अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) नीति आयोग ने राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उपयोग करके 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति के आकलन हेतु एसडीजी इंडिया इंडेक्स विकसित किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत करता है तथा प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नवीनतम प्रकाशन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, में केरल को 79वें समग्र स्कोर के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित पर https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(ग) भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है जैसा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से पता चलता है और अंतर-राज्यीय विकास असमानताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार देश में गरीबी को कम करने के लिए कई योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। कुछ योजनाओं का उद्देश्य संसाधनों/धन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे नागरिकों को लाभान्वित करना है, जबकि अन्य का उद्देश्य सक्षम बुनियादी ढांचागत प्रावधान तैयार करना है। इनमें विकसित भारत – रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी), आदि शामिल हैं।

(घ) नीति आयोग ने सरकारी योजनाओं के अभिसरण, प्रमुख निष्पादन संकेतकों की निगरानी तथा जिलों एवं ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर नागरिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) तथा वर्ष 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) प्रारंभ किया। केरल एक जिला वायनाड तथा 9 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आकांक्षी जिलों एवं आकांक्षी ब्लॉकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उन्हें निर्धारित संकेतकों पर की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है जो क्रमशः एडीपी के लिए *चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/)and(https://abp.championsofchange.gov.in/)* पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

केरल में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल ब्लॉकों की जिला-वार सूची अनुलग्नक में संलग्न है।

नीति आयोग 'राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)' का भी कार्यान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (एसआईटी) की स्थापना अथवा विद्यमान राज्य आयोजना विभागों/बोर्डों की भूमिका की पुनर्परिकल्पनाइदउ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे राज्यों की विकास कार्यनीतियों का मार्गदर्शन करने वाले बहुविषयक संसाधन केंद्रों के रूप में कार्य कर सकें। अब तक की स्थिति के अनुसार केरल राज्य सरकार ने अपने राज्य में राज्य सहायता मिशन का कार्यान्वयन नहीं किया है।

अनुलग्नक

क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा दिनांक 10.08.2026 के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2533 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल के आकांक्षी ब्लॉकों की सूची

क्रम सं.	**जिले का नाम**	**ब्लॉक का नाम**
1	इडुक्की	अज़ूथा
2		देविकुलम
3	कासरकोड	परप्पा
4	पालक्काड	अट्टप्पाडी
5		कोल्लंगोड
6	वायनाड	कल्पेट्टा
7		मानंथवाडी
8		पनामरम
9		सुल्तान बथेरी

*****